

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उद्यान भवन चौबटिया-रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक, 03 दिसम्बर 2015

विषय-चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में "सी" ग्रेड माल्टा का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्यान विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 879 XVI-1/15/5(29)/2015 दिनांक 20 अगस्त 2015 के क्रम में, राज्य में माल्टा फसल के उत्पादकों को उनकी उपज का अपेक्षित मूल्य प्रदान किये जाने के उद्देश्य से, उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु राज्य में उत्पादित "सी" ग्रेड माल्टा फसल हेतु रु 7000.00 प्रति मैट्रिक टन (रु 7.00 प्रति किलो) की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए कृषकों/फल उत्पादकों से क्रय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. "सी" ग्रेड माल्टा की फसल के उपार्जन हेतु घोषित उपरोक्त मूल्य कुल अनुमानित मात्रा 1500 मैट्रिक टन अथवा वास्तविक मात्रा जो भी कम हो, की सीमान्तर्गत अनुमन्य होगी। उक्त उपार्जन का कार्य जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर में स्थापित उद्यान विभाग के निर्धारित संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा। सम्बन्धित केन्द्रों पर जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा अस्थाई रूप से कार्मिकों की तैनाती समयबद्ध रूप से कर ली जायगी तथा मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
2. उक्त फसल के उपार्जन के कार्य की अवधि दिनांक 01 दिसम्बर 2015 से दिनांक 31 जनवरी 2016 तक प्रभावी होगी।
3. योजना केवल उद्यान कार्डधारक उद्यानपतियों हेतु प्रभावी होगी। ठेकेदार एवं बिचौलिये इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे। क्रय किये जाने वाले "सी" ग्रेड माल्टा फल का न्यूनतम आकार 50 मि0मी0 व्यास से कम नहीं होना चाहिए, एवं फल आंशिक सड़े-गले, कटे, फटे नहीं होने चाहिए एवं फसल पुनः विक्रय योग्य होनी चाहिए। फल 20 किग्रा0 क्षमता के प्लास्टिक क्रेट्स में उद्यानपतियों से प्राप्त किये जायेंगे।

-2-.....

तुड़ाई उपरान्त फलों में वाष्पीकरण एवं श्वसन क्रिया के परिणामस्वरूप वजन में होने वाली कमी के दृष्टिगत उपार्जन कर के समय तौल में 2.5 प्रतिशत अधिक वजन लिया जायेगा।

4. उक्त उपार्जन का कार्य उद्यान विभाग, एवं विभाग के अन्तर्गत संचालित उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन बोर्ड के सहयोग से किया जायेगा, उक्त कार्य में आवश्यकता पड़ने पर अन्य संस्थाओं यथा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम का सहयोग प्राप्त किया जाय। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार, सुनिश्चित किया जाय।
5. सम्बन्धित उत्पादकों को उपरोक्त घोषित समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होने की स्थिति में वे अपनी "सी" ग्रेड माल्टा फसल का विक्रय करने हेतु स्वतंत्र होंगे। उद्यान विभाग द्वारा उपार्जित "सी" ग्रेड माल्टा फसल को भण्डारणोपरांत अथवा ताजे उपार्जित फलों को राज्य के भीतर तथा बाहर स्थापित मण्डियों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की प्रसंस्करण इकाईयों को विक्रय किया जायेगा यदि समर्थन मूल्य या इससे अधिक मूल्य स्थानीय बाजारों में प्राप्त होता है तो इसे नीलामी द्वारा प्रथम प्राथमिकता पर विक्रय किया जायेगा। फलों के विक्रय से प्राप्त आय को सम्बन्धित सुसंगत लेखाशीर्षक में तत्काल जमा किया जायेगा एवं सम्पूर्ण भुगतान एकाउन्ट पेई चैक के माध्यम से किया जाय।
6. उक्त उपार्जन कार्य का सम्पूर्ण क्रियान्वयन नियमानुसार उद्यान विभाग के अन्तर्गत संचालित उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन बोर्ड को चक्रीय निधि के रूप में स्वीकृत रु 10.00 करोड़ की धनराशि से किया जायेगा एवं विभाग द्वारा कर/उपार्जित उक्त फसल के उपार्जन कार्य में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
7. उक्त आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आ0श0 संख्या 50(i)/XXVII-4-15 दिनांक 27 नवम्बर 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)

अपर सचिव।

क्रमशः-03

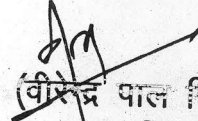
(3)

संख्या- 1963, XVI-1/15/5(29)/201 दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
4. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
6. उप निदेशक, उद्यान विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. जिला उद्यान अधिकारी, जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड औद्योगिक विपणन परिषद, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(वीरेंद्र पाल सिंह)
उप सचिव।